

squatters—like other squatters who started squatting after July 1960—were being treated as ineligible squatters and charged economic rent at Rs. 5.00 p.m. instead of the subsidised rent of Rs. 3.50 p.m. charged from the eligible squatters. It was, however, decided in February 1965 that the squatters whose names are included in the Voters list of January 1961 should also be charged the subsidised rent of Rs. 3.50 per mensem. This decision will shortly be implemented in both the Naraina and Madangir colonies.

Southern Grid

5519. Shri Brij Basi Lal:

Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Conference of Chairmen of State Electricity Boards and Chief Engineers of four Southern States decided on the 25th April, 1966 at Hyderabad to give top priority in the construction of six power lines to establish the southern grid;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the total amount of expenditure on such projects?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Yes,

(b) The Government of India are in agreement with the decisions arrived at the Conference.

(c) About Rs. 23.34 crores

असहाय रोगियों की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लिया जाना

5520. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असहाय रोगियों की जरूरत की 'कोलोस्टोमी

भाउटफिट" जैसी वस्तुओं पर भी भारी सीमा शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का ध्यान इस कठिनाई को धोर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शशीन्द्र चौधरी) :

(क) ऐसे सामान पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर को, मूल्य के अनुसार, 60 प्रतिशत का कानूनी दर के मुकाबले में घटा कर मूल्य के अनुसार 25 प्रतिशत और इसके साथ उस पर मूल्य के अनुसार 10 प्रतिशत का नियामक सीमा शुल्क, कर दिया गया है।

(ख) इस शुल्क से भी छूट पाने के लिए हाल ही में सरकार के पास एक व्यक्ति की प्रार्थना आई है।

(ग) सरकार एतदर्थ इस सीमा शुल्क से बिल्कुल ही मुक्त करने के लिए तैयार है बशर्ते कि सरकार को इस बात की तसल्ली हो जाय कि यह वास्तव में एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को बिना मूल्य दान रूप में दी जा रही है। इस सूचना की प्रतीक्षा है।

Laxmi Bank of Akola

5521. Shri R. Barua: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government have taken any action against the management of the Laxmi Bank of Akola which has been recently liquidated; and

(b) whether Government have constituted an enquiry into the causes which led to the liquidation of the said Bank?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). The chairman and certain other officers of the bank have already been tried and have been convicted